basis from the recent enhancement of postal charges;

(b) the proportion of this additional burden likely to be placed on economically disadvantaged sections; and

(c) whether Government have any proposal to supply at subsidised rates post cards and inland letters to low-income groups through the public distribution system?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI JAGMOHAN): (a) The total additional revenue expected to be collected in a financial year from the recent enhancement of postal charges effective from 31st August, 1998 is Rs. 272 crores.

(b) The impact of revision of tariff in respect of 8 Postal Services, namely, Competition Post Card, Letter Cards, Letters, Parcels, Registration, Insurance, Acknowledgement and Money Order Form is likely to be minimal on economically disadvantaged sections as no tariff revision has been effected in the case of Post Cards and in the rate of Money Order commission which are generally used by them. Even in respect of the 8 Postal Services, the revision of tariff has been marginal in order to partly meet the increased cost of operations of various services requiring considerable subsidy from the General Budget.

(c) No, Sir.

Undertaking from Private Telecom Operators

*177. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister's Office has asked the department of Telecommunications to take undertakings from private telecom operators who have defaulted in paying licence fee for cellular or basic service;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) its effect on private telecom operators?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI JAGMOHAN): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise in view of (a) above.

Alternate Route for Kailash-Mansarover Yatra

*178. SHRI NARENDRA MOHAN: SHRI SANJAY NIRUPAM:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be please to state:

(a) whether Government are thinking of opening an alternate route for Kilash Mansarovar Yatra in view of the recent mishap resulting in tragic death of about 200 persons at Malpa en-route to Kailash-Mansarovar Yatra;

(b) if so, whether any survey has been conducted and with what results; and

(c) whether Government will also take into consideration the old traditional route through Tunjaun pass in Garhwal Himalayas?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (c) On August 18, 1998 205 people, Including 60 yatris of the 12th batch of the Kallash Mansarovar Yatra were killed in a landslide which engulfed Malpa village in Pithoragarh District of Uttar Pradesh.

Taking into account the growing popularity of the Yatra amongst Hindu pilgrims, the constraints along the existing route, and requests from residents in the border areas, the Government have taken up, since 1993, proposals for an alternate/additional route for the Kailash Mansarovar Yatra with the Chinese side. We have proposed the Shipki La (Himachal Pradesh), and Demchok (Ladakh, Jammu & Kashmir) routes. We have proposed these routes taking into account the existing logistical facilities which extend almost upto the border.

The Chinese response has been that our proposals for alternative routes are under consideration in consultation with the local authorities in the Tibet Autonomous Region (TAR). They have cited difficulties in opening new routes on the grounds that it would involve travel over much longer distances over difficult terrain with poor road conditions, and, lack of proper infrastructure for accommodation and communications. They have also expressed the view that development of infrastructure in these remote areas would not be an easy task and building facilities for alternative routes could take a long time.

Tunjun Pass is located in the Barahoti area of the Chamoli District of Uttar Pradesh. Since the fifties, China has claimed that this Pass is located on the Chinese side.

Government of India, for its part, are willing to consider new routes talking into account the availability of infrastructure and logistical facilities and other relevant factors. Our efforts to open a new route are continuing.

पानी के लिए संघर्ष

*179. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भू-वैज्ञानिकों का विश्वास है कि इक्कीसवीं सदी पानी के लिए संघर्ष की सदी होगी; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि और तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण 21वीं सदी में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में और अधिक कमी आयेगी। स्वतंत्रता के समय देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता प्रति वर्ष 5000 वर्ग घन मीटर से अधिक थी जो अब घटकर 2200 घन मीटर प्रति वर्ष रह गई है और यह अनुमान लगाया गया है कि यह उपलब्धता सन् 2025 तक घट कर लगभग 1500 घन मीटर रह जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के मानदण्ड के अनुसार 1000 घन मीटर प्रति व्यक्ति से कम जल उपलब्धता वाली स्थिति को जल की कमी वाली स्थिति माना जाता है। इसलिए सन् 2025 के अंत में भारत के सामने राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः जल की कमी की स्थिति नहीं होगी। तथापि, कुछ नदी बेसिन स्तर अथवा स्थानीय स्तर पर जल की कमी की स्थिति है।

भविष्य में प्रति व्यक्ति घटती हुई जल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न नीति और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें राष्ट्रीय जल नीति अपनाना, अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का हस्तांतरण करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल के कुशल और किफायती उपयोग को बढ़ावा देना और उसका संरक्षण करना तथा चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। सरकार वर्षा के जल पर आधारित खेती और वाटरशेड प्रबंधन को भी बढ़ावा दे रही है।

प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा

*180. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कब तक लागू करना चाहेगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कादाम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:—

1. सभी मंत्रालय/विभाग उनके द्वारा प्रशासनिक